(e) if so, what are the details thereof; and

(f) the manner in which the Central Government propose to meet the existing financial crisis in the State and to retrieve the poverty and unemployment situation in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (f) Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Fake Share Transfer Stamps

1625. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state·

(a) whether Government's attention has been drawn to a scam worth Rs. 50 crore in fake share transfer stamp in operation in four metropolitan cities of the country;

(b) if so, whether Government have enquired into the scam;

(c) if so, what are the findings of the enquiry and details of those involved in the scam; and

(d) what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

गुजरात राज्य में पालिटेकनीकों के विकास के लिये विश्व बैंक सहायता

1626 **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षावार, विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषक विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत गुजरात राज्य में पालिटेकनिकों के विकास के लिए गुजरात राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) गुजरात में प्रत्येक पालिटेकनिक ने कितनी धनराशि इस्तेमाल की है; और

(ग) वे उद्देश्य कौन से हैं जिनके लिये प्रत्येक मामले में उक्त धनराशि का उपयोग किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० अबरार अहमद (क) विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित की जा रही तकनीकी शिक्षा परियोजना के अंतर्गत गुजरात को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। इस परियोजना के अंतर्गत गुजरात को जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

1990–91	शून्य
1991–92	274.21 लाख रुपए
1992–93	756.48 लाख रुपए

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा किए गए पुनःपूर्ति दावों के आधार पर विश्व बैंक व्यय की विनिर्दिष्ट सहम श्रेणियों के लिए संवितरण करता है प्रत्येक पोलीटकनिक द्वारा ऐसी सहायता के उपयोग का ब्यौरा राज्य सरकार पास उपलब्ध होगा।

Improvement in financial system

1627. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister FINANCE be pleased to state:

(a) what steps have been taken Government to bring about improvement and efficiency in the financial system;

(b) what is extent to which external constraints have been eased and

(c) what new measures have been enforced for improving customer service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) The Government had constituted the Comfittee on the Financial System under the Chairmanship of Shri M. Narasimham to examine all aspects relating to the structure, organisation, functions and procedures of the financial system. The Committee submitted its report on 20th November, 1991. Initiatives taken pursuant to the Committee's recommendations include reduction in Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Cash Reserve Ratio (CRR), simplification of interest rate structure, positioning of norms in respect of capital adequacy, income recognition and provisioning requirements, revision of balance sheet and profit and loss formats for ensuring greater transparency, revision of Reserve Bank of India guidelines for branch licensing initiation of process of converting Industrial Finance Corporation of India (IFCI) into a company, issue of guidelines on entry of new private sector banks, measures aimed at liberalisation of the capital market, vesting of SEBI with statutory powers, equal treatment of various Mutual Funds in the area of tax concessions etc. Government have decided to implement the recommendations of the Committee in a phased manner.

(c) The Goiporia Committee in its report submitted to Reserve Bank of India in 1991 had made wide ranging recommendations covering (i) improvement of customer service by enlarging the scope of teller services, extending banking hours for non-cash transactions, devising appropriate procedures to render uninterrupted service during business hours; (ii) opening of specialised branches focussing on internatinoal banking industrial finance, small scale industries, (iii) te hnology upgradation and continuous review of systems and procedur in tune with the changing needs of customers; and (iv) compensating customers for delay in collection of cheques, payment by mail transfer, telegraphic transfer, etc.

Reserve Bank of India have already issued necessary instructions in respect of several recommendations of the Committee.

ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की योजनायें

1628. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने बड़े पैमाने पर ग्रामीण उद्योगों को स्थापित करके ग्रामीण लोगों की सहायता उपलब्ध करने के लिए कोई योजना तैयार की है जिससे गुजरात में रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन में भी सहायता मिले ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की गुजरात राज्य के लिए निकट भविष्य की क्या योजनायें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि उनकी योजनायें किसी राज्य विशेष के संदर्भ में नहीं होती हैं और गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र अति लघु और लघु उद्योग क्षेत्रों को उसकी पुनर्वित्त सहायता के तहत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार दी गई सहायता से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों सहित सारे देश में रोजगार की सुविधा बढ़ी है। अपने तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान सिडबी ने गुजरात में लघु उद्योग क्षेत्र को 1168.11 करोड़ रुपए की कुल सहायता मंजूर की।